

भारतीय कृषि का रूपांतरण

यह एडिटरियल 24/06/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“How Shivraj Singh Chouhan can transform Indian agriculture”](#) लेख पर आधारित है। इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित चुनौतियों की चर्चा की गई है और भारत की नवगठित सरकार के लिये संभावित समाधानों का सुझाव दिया गया है।

प्रलिमिस के लिये:

[कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय \(MoA&FW\)](#), [सार्वजनिक वितरण प्रणाली \(PDS\)](#), [लघु एवं सीमांत कृषि \(SMF\)](#), [कृषि जनगणना](#), [प्रधानमंत्री कृषि समान नधि \(PM-KISAN\)](#), [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#), [मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना](#), [प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना \(PMKSY\)](#), [ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार \(e-NAM\)](#)

मेन्स के लिये:

भारत में कृषि का महत्त्व, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, कृषि से संबंधित प्रमुख पहल, भारत में कृषि क्षेत्र के सुधार हेतु आगे की राह।

हाल ही में शिवराज सहि चौहान को नवगठित सरकार में [कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय \(MoA&FW\)](#) और [ग्रामीण विकास मंत्रालय](#) का प्रभार सौंपा गया है।

उनकी नियुक्ति उनके सदिध ट्रैक रिकॉर्ड और कृषि एवं ग्रामीण विकास की गहरी समझ के कारण रणनीतिक महत्त्व रखती है। उन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में राज्य ने वर्ष 2005-06 से 2023-24 तक प्रतिवर्ष 7% की जीडीपी वृद्धि और 6.8% प्रतिवर्ष की कृषि-जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही।

MoA&FW को भारतीय कृषि क्षेत्र के समक्ष वदियमान उन दबावपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिये तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है जो ग्रामीण विकास एवं समग्र आर्थिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसकी सबसे प्रमुख प्राथमिकता 5% से अधिक की वार्षिक कृषि-जीडीपी वृद्धि हासिल करना और किसानों की आय में तेज़ी से वृद्धि करना होना चाहिये।

भारत में कृषि का महत्त्व:

■ जीडीपी में योगदान:

- पछिले कुछ दशकों में भारत की [जीडीपी](#) में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है लेकिन यह क्षेत्र अभी भी एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।
- अर्थव्यवस्था के [कुल सकल मूल्यवर्द्धति \(GVA\)](#) में कृषि की हस्तिसेदारी वर्ष 1990-91 के 35% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15% रह गई है। यह गिरावट कृषि GVA में गिरावट के कारण नहीं बल्कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र GVA में तेज़ी से वसितार के कारण आई है।

■ रोज़गार:

- कृषि क्षेत्र, देश में सबसे बड़ा नयिकता होने की स्थिति रखता है।
- [सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय \(MoSPI\)](#) के [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय \(NSSO\)](#) द्वारा आयोजित [आवधिकी श्रम बल सर्वेक्षण \(PLFS\)](#) के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न था।

■ खाद्य सुरक्षा:

- भारत मुख्य खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से चावल और गेहूँ के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश अपनी बढ़ती आबादी को खाद्य प्रदान कर सकता है।
 - भारत दूध, दाल और मसालों का [वर्ष का सबसे बड़ा उत्पादक](#) है, जबकि यहाँ वशिष की सबसे बड़ी मवेशी आबादी (भैंस) पाई जाती है। इसके साथ ही भारत में गेहूँ, चावल और कपास की खेती के लिये कुल भूमिका सबसे बड़ा क्षेत्र मौजूद है।
 - भारत [चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ एवं बकरी का माँस, फल, सब्जियाँ और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक](#)

है।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** और खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम जैसी सरकारी पहलें सभी नागरिकों को कफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिये कृषि उत्पादन पर निर्भर करती हैं।
 - PDS के तहत वर्तमान में गेहूँ, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी वस्तुओं को लाभार्थियों के बीच वितरण हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित किया जा रहा है।
 - कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेश PDS आउटलेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपभोग की अन्य वस्तुएँ (जैसे दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि) भी वितरित करते हैं।

■ भूमि उपयोग:

- भारत में कृषि भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से कुछ अधिक है। यह विश्व के किसी भी देश में कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है।
- देश में लगभग 195 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जिसमें से लगभग 63 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है (लगभग 125 मिलियन हेक्टेयर) जबकि 37 प्रतिशत सिंचित (70 मिलियन हेक्टेयर) है।

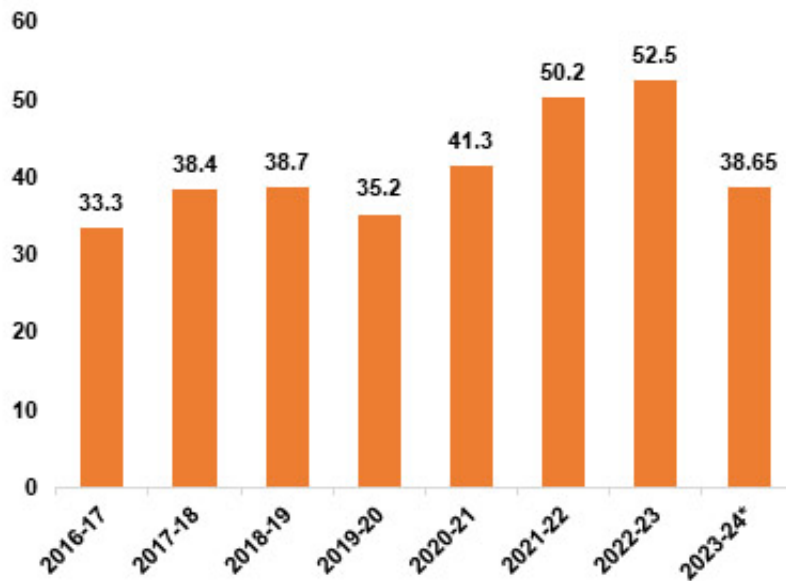
■ वदेशी मुद्रा:

- कृषि निर्यात भारत की वदेशी मुद्रा आय अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चावल, मसाले, कपास, फल और सब्जियाँ जैसी वस्तुओं का वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जाता है, जिससे राजस्व प्राप्त होता है और व्यापार घाटे को संतुलित किया जाता है।
- अप्रैल-जनवरी 2024 में कृषि उत्पादों के निर्यात का कुल मूल्य 38.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वर्ष 2022-23 में भारत से कृषि निर्यात 52.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रहा।

■ सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संवहनीयता:

- कृषि भारत की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक ताने-बाने से गहराई से संबंधित है। यह ग्रामीण परंपराओं, त्योहारों और सामुदायिक जीवन को आकार देती है तथा यह सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण सामंजस्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- मृदा की उर्वरता, जल और जैवविविधता जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिये संवहनीय कृषि पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक खेती के तरीके और आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और दीर्घकालिक संवहनीयता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती हैं।

India's agriculture exports trend (US\$ billion)



Note: *Until January 2024

Source: The Ministry of Commerce & Industry

भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

■ छोटी भूमि जोत:

- भारत में कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग छोटी जोतों में वितरित है, जो किसानों की सम्मानजनक आजीविका कमाने की क्षमता को सीमित करता है।
- कृषि जिनगणना से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, परिचालन जोतों का औसत आकार वर्ष 1970-71 के 2.28 हेक्टेयर से घटकर वर्ष 1980-81 में 1.84 हेक्टेयर, वर्ष 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर और वर्ष 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया है।
- भारत की कृषि जिनगणना 2015-16 के अनुसार, 86.1 प्रतिशत भारतीय किसान **छोटे और सीमांत किसान (SMF)** हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।

■ आर्थिक कठिनाइयाँ:

- भारत में एक किसान की औसत मासिक आय अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जो कृषि क्षेत्र में उन लोगों के समक्ष वदियमान आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है।
 - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की वर्ष 2019 की एक रपिर्ट के अनुसार, मजदूरी, फसल उत्पादन और पशुधन सहित सभी स्रोतों से प्राप्त एक किसान परिवार की औसत मासिक आय लगभग 10,218 रुपए थी।
- छोटे और सीमांत किसानों को प्रायः ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कफायती ऋण की सीमिति उपलब्धता आधुनिक कृषि उपकरण, गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों में नविश करने की उनकी क्षमता को सीमिति करती है, जिससे उनकी उत्पादकता में बाधा आती है।
 - वर्ष 2019 में आयोजित NSS सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में आधे से अधिक कृषक परिवार ऋणग्रस्त हैं।

■ मृदा क्षरण और जल की कमी:

- कृषि के लिये जल का अत्यधिक दोहन जलभृतों में जल स्तर को कम कर रहा है, जिससे प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में संचाई करना असंभव होता जा रहा है।
 - भारत के लगभग 90 प्रतिशत भू-जल का उपयोग कृषि के लिये किया जाता है
- अनुचित भूमि उपयोग प्रथाएँ, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अपर्याप्त मृदा संरक्षण उपाय मृदा क्षरण एवं कटाव में योगदान करते हैं।
 - इनके कारण मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, कीटों एवं बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और अंततः कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है।

■ अपर्याप्त कृषि अवसंरचना:

- अपर्याप्त भंडारण एवं कोलुड चेन सुवधायें, अपर्याप्त ग्रामीण सड़कों और बाजारों तक सीमिति पहुँच, उत्पादन के बाद होने वाली हानि (post-harvest losses) में योगदान करती हैं।
- इन अवसंरचना अंतरालों के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और किसानों की अपनी उपज के लिये उचित मूल्य प्राप्त करने की क्षमता सीमिति हो जाती है।

■ कृषि अनुसंधान में नमिन नविश:

- कृषि अनुसंधान और वसितार सेवाओं में नविश मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, जिससे वास्तविक वित्तपोषण में कमी आई है।
- इस नमिन नविश के कारण नवोन्मेषी और कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।

■ पुरानी पड़ चुकी कृषि पद्धतियाँ:

- भारतीय किसानों का एक बड़ा हस्सिा अभी भी पारंपरिक और पुरानी पड़ चुकी कृषि पद्धतियों पर निर्भर है।
- सूचना तक सीमिति पहुँच, आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी और बदलाव के प्रति प्रतिरोध, उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- कृषि अनुसंधान में नमिन नविश के कारण नवोन्मेषी और कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न होती है।

■ बाजार की अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव:

- भारत में किसानों को प्रभावी बाजार संपर्कों, बचौलियों और मूल्य सूचना की कमी के कारण मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इससे वे मूल्य शोषण और अपने नविश पर अनश्चिति रटिर्न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- भारतीय नीति निर्माता प्रायः प्रतिकूल WTO नरिण्यों के प्रभावों को समझने और उसे कम करने के लिये संघर्ष करते हैं।
- उपभोक्ताओं के लिये खाद्य कीमतों को कम रखने की वैश्विक प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से फार्म-गेट मूल्यों में कमी आती है, जिससे खेती आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और पर्यावरणीय रूप से असंवहनीय हो जाती है।

■ वषिम नीतगित चुनौतियाँ:

- नीतगित चुनौतियाँ इसलिये सामने आती हैं क्योंकि सरकार सार्वजनिक वतिरण प्रणाली के माध्यम से बहुत कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराती है। इससे किसानों को उनकी फसलों के लिये मलिन वाली कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे उनके लिये पर्याप्त आय अर्जति करना कठिन हो जाता है।
- इसके अतिरिक्त, वषिम उर्वरक सब्सिडी इसके अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संवहनीयता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

■ जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:

- बढ़ते हुए अनयिमिति मौसम पैटर्न ने कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया है।
- अपरत्याशति मौसम पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और बाढ़, चक्रवात एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भारत के कृषि उद्योग के लिये गंभीर चुनौतियाँ पेश करती हैं। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप फसल की हानि, पशुधन की मौत और किसानों के लिये भेद्यता बढ़ सकती है।
- जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन के अनुसार, अनुकूलन उपायों को अपनाए बना, भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार वर्ष 2050 तक 20% और वर्ष 2080 तक 47% कम हो जाने का अनुमान है।

कृषि से संबंधित प्रमुख पहलें:

- प्रधानमंत्री किसान सममान नधि (PM-KISAN)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना (PMKSY)
- ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

कार्यक्रम/परियोजना	मंत्रालय

1. सूखा - प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3. वर्षा पूर्ति क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संचयन विकास परियोजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 (b) केवल 3
 (c) 1, 2 और 3
 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से कसि कृषि में सार्वजनिक निविश माना जा सकता है? (2020)

1. सभी फसलों की कृषि उपज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूंजी का विकास
4. किसानों को निःशुल्क वित्तियुत आपूर्ति
5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफी
6. सरकारों द्वारा शीत भण्डारण सुविधाओं की स्थापना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
 (b) केवल 1, 3, और 4 और 5
 (c) केवल 2, 3 और 6
 (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: C